[2023] 14 एस.सी.आर. 153: 2023 आईएनएससी 964

वाद का विवरण

कुम. गीता, पुत्री दिवंगत कृष्णा एवं अन्य

बनाम

नंजुंदास्वामी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 7413/2013)

31 अक्टूबर, 2023

[पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा और सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्तिगण]

शीर्ष टिप्पणियाँ

विचारणीय मुद्दा: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII, नियम 11 की अस्वीकृति के अंतर्निहित सिद्धांत का सही अनुप्रयोग, मामले के तथ्यों और आंशिक रूप से एक वादी की अस्वीकृति की वैधता के लिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेशVII, नियम 11-याचिकाओं की अस्वीकृति-अंतर्निहित सिद्धांत- वादी और प्रतिवादी संख्या 1-3 का आवेदन एक संयुक्त परिवार के सदस्य थे जो वादी की अनुसूची क और ख में उल्लिखित संपत्तियों के मालिक थे- वादी ने विभाजन और अलग कब्जे के लिए वाद का नेतृत्व किया-वादी के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए अभियोग आदेश VII, नियम11, सीपीसी को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था- उच्च न्यायालय ने आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी, और अनुसूची-क संपत्ति के संबंध में याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उसमें वर्णित संपत्ति 1919 में एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से बेची गई थी और वादी ने बिक्री से इनकार नहीं किया था-वैधताः

अभिनिर्धारित: सही परीक्षण सबसे पहले वादी को सार्थक रूप से और समग्र रूप से पढ़ने के लिए है, इसे सही मानते हुए-इस तरह के पढ़ने पर, यदि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है, तो आवेदन आदेश VII, नियम 11 विफल होना चाहिए- वादी को अस्वीकार कर

दिया जाएगा जहां वह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है- वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने मामले के गुणागुण की जांच करके त्रुटि की- इसने बिक्री विलेख की सच्चाई, वैधता और वैधता का पूर्व निर्णय लिया जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 4 से 14 दावा शीर्षक- उच्च न्यायालय यह मानकर अभिकथनों की सच्चाई का अनुमान नहीं लगा सकता था कि संपत्ति की कथित पूर्व बिक्री पूरी हो गई है या उस पर कार्रवाई की गई है-उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण गलत है और अनुसूची-क संपत्ति के संबंध में वाद को आंशिक रूप से अस्वीकार करने और वादी को केवल अनुसूची-ख संपत्ति के संबंध में मामले पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने में त्रुटिपूर्ण है-य ह दृष्टिकोण अस्वीकार्य है- संशोधन याचिका में पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-आवेदन आदेश VII, नियम 11 खारिज कर दिया गया, मुकदमा यहां तक कि याचिका की अनुसूची क के तहत उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में भी बहाल किया गया। [अनुच्छेद 7,10-13]

उद्धरणो और अन्य संदर्भों की सूची

दहीबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुशाली (2020) 7 एससीसी 366: [2020] 5 एससीआर 694; सेजल ग्लास लिमिटेड बनाम नविलन मर्चेंट्स (पी) लिमिटेड (2018) 11 एससीसी 780: [2017] 7 एससीआर 557; माधव प्रसाद अग्रवाल बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड (2019) 7 एससीसी 158:2019.8 एससीआर 1058-पर भरोसा किया गया।

आक्षेपित आदेश और उपस्थिति सहित अन्य मामले का विवरण

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7413/2023

सीआरपी संख्या 158/2010 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 09.11.2015 के निर्णय और आदेश से।

अधिवक्तागण:

पी. वी. योगेश्वरन, एम. ए. चिन्नासामी, श्रीमती सी. रुबावती, सी. राघवेंद्रन, वी. सेंथिल कुमार, देवेंद्र प्रताप सिंह, आशीष उपाध्याय अधिवक्तागण, अपीलार्थियों के लिए।

नंदकुमार, सुश्री दीपिका नंदकुमार, अशोक कुमार सिंह, राजीव गुप्ता, नरेश कुमार, अधिवक्ता। प्रतिवादियों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्तिगण

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में, हमें दो प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। पहला आदेश आदेश VII नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता, 19081 के तहत मामले के तथ्यों के लिए 'वाद पत्रों की अस्वीकृति' के अंतर्निहित सिद्धांत के सही और सही अनुप्रयोग से संबंधित है। दूसरा प्रश्न आंशिक रूप से वाद की अस्वीकृति की वैधता से संबंधित है। अनुवर्ती कारणों के लिए, हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि की है। पहला, सीपीसी के आदेश VII नियम 11 को सूचित करने वाले सुस्थापित सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू करना, और दूसरा, वाद को आंशिक रूप से अस्वीकार करना, जो फिर से इस विषय पर कानून के विपरीत है। इसलिए हमने अपील को स्वीकार कर लिया है और आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत आवेदन को खारिज कर दिया है। हम सबसे पहले आवश्यक तथ्यों का संकेत देंगे।

3. श्री पी वी योगेश्वरन, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री एम. ए. चिन्नासामी, श्रीमती सी. रुबावती, श्री सी. राघवेंद्रन, श्री वी. सेंथिल कुमार, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह और श्री आशीष उपाध्याय की सहायता से, ने कहा कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जिनके पास शिकायत की अनुसूची क और ख में उल्लिखित संपत्तियां हैं। उन्होंने हमें उस शिकायत के माध्यम से लिया है जिसमें यह कहा गया है कि परिवार के कर्ता स्वर्गीय श्री मुनिवेनकता भोवी के पास कई संपत्तियां थीं और

उन्हें 'नाममात्र बिक्री विलेख' के रूप में संदर्भित कार्यों को निष्पादित करके जागीर जुटाने के लिए अस्थायी रूप से संपत्तियों को गिरवी रखने की आदत थी। एक बार बकाया राशि का भुगतान हो जाने के बाद, पुनर्भरण विलेखों को निष्पादित किया गया। यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि इस प्रथा को कर्ता द्वारा विभाजन और अलग अधिकार के लिए बनाए रखने के लिए अपनाया गया था और जिन व्यक्तियों के पक्ष में इन दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था, वे भी परिवार के करीबी परिचित थे। इस प्रकार, संयुक्त परिवार की संपत्तियों का कब्जा कभी भी विभाजित नहीं किया गया था। यह भी दलील दी जाती है कि जब वादी ने विभाजन के लिए कहा, तो शुरू में प्रतिवादियों ने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि इसके बजाय, वादी को केवल राजस्व रिकॉर्ड के अद्यतन होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा ताकि वास्तविक विभाजन को प्रभावी बनाया जा सके। इसलिए, वादी ने विभाजन और अलग अधिकार के लिए एक वाद प्रस्तुत किया।

4. मुकदमा शुरू होने के चार साल बाद, प्रतिवादियों ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र को खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। जबकि ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कहा कि सर्वेक्षण संख्या 76/1 (वादी की अनुसूची क में वर्णित) की संपत्ति 1919 में एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से बेची गई थी। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि वादी ने बिक्री से इनकार नहीं किया, बल्कि केवल यह आग्रह किया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप उत्परिवर्तन के बिना, संपत्ति को संयुक्त परिवार में वापस भेज दिया जाए। इस तथ्य से प्रभावित होकर कि वादी ने न तो 1919 से बिक्री विलेख को चुनौती देने के लिए कोई सबूत पेश किया, न ही बिक्री विलेख के खिलाफ कोई घोषणात्मक राहत मांगी, उच्च न्यायालय ने आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति देने के लिए आगे बढ़े, और अनुसूची-क संपत्ति के संबंध में वाद को खारिज कर दिया। श्री योगेश्वरन ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने संशोधन की अनुमति देने में त्रुटि की और परिणामस्वरूप, आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत आवेदन दिया।

5. दूसरी ओर, सुश्री दीपिका नंदकुमार, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री राजीव गुप्ता और श्री नरेश कुमार की सहायता से, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. नंदकुमार ने उच्च न्यायालय के तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया।

6. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की वैधता पर विचार करने से पहले, आदेश VII नियम 11, सीपीसी2 और विषय पर मिसालों पर विचार करना आवश्यक है। दहिबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाली,[3] में इस न्यायालय के हालिया फैसले में प्रासंगिक सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार समझाया गया है:

"23.2. आदेश 7 नियम 11 के अधीन उपचार एक स्वतंत्र और विशेष उपचार है, जिसमें न्यायालय को साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए कार्यवाही किए बिना और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचारण किए बिना, यदि यह संतुष्ट किया जाता है कि कार्रवाई को इस उपबंध में निहित किसी भी आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए, तो किसी वाद को संक्षिप्त रूप से खारिज करने का अधिकार है।

23.3. आदेश 7 नियम 11 (क) का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि यदि किसी वाद में कार्रवाई का कोई कारण प्रकट नहीं किया जाता है, या नियम 11 (घ) के तहत वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो अदालत वादी को वाद में कार्यवाही को अनावश्यक रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी। ऐसे मामले में, नकली मुकदमेबाजी को समाप्त करना आवश्यक होगा, ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो।

23.4. अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी में [अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, 1986 सप्लीमेंट एससीसी 315। मानवेंद्रसिंहजी रणजीतसिंहजी जडेजा बनाम विजयकुंवरबा, 1998 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 281: (1998) 2 जीएलएच 823] में निम्नलिखित न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस उपबंध के अधीन शक्तियों को प्रदान करने का संपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो मुकदमा अर्थहीन है, और निष्फल सिद्ध होने के लिए बाध्य है, उसे न्यायालय का न्यायिक समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, निम्नलिखित शब्दों में: (एससीसी पृष्ठ 324, अनुच्छेद 12)

"12. ... ऐसी शक्तियों को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो अर्थहीन है, और विफल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे अदालत के समय पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और प्रतिवादी के दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। डेमोक्लिस की तलवार को बिना किसी उद्देश्य के अनावश्यक रूप से उसके सिर पर लटकाए रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि एक साधारण दीवानी मुकदमे में,

अदालत आसानी से एक वाद को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग करती है, अगर वह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है।

23.5. हालांकि, एक दीवानी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अदालत को दी गई शक्ति एक कठोर है, और आदेश 7 नियम 11 में उल्लिखित शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

23.6. आदेश 7 नियम 11 के तहत, यह निर्धारित करने के लिए अदालत पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि क्या वादी अभियोग [लिवरपूल और लंदन एस. पी. और एसोसिएशन लिमिटेड बनाम एम. वी. सी सक्सेस, (2004) 9 एससीसी 512] में कथनों की जांच करके कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है।], उन दस्तावेजों के साथ पढ़ा गया जिन पर भरोसा किया गया था, या क्या मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है।

.. ..

23.9. इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालत यह निर्धारित करेगी कि क्या वाद में किए गए दावे वैधानिक कानून या न्यायिक आदेश के विपरीत हैं, यह तय करने के लिए कि क्या वाद को खारिज करने का मामला सीमा पर बनाया गया है।

23.10. इस स्तर पर, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलें और गुण-दोष के आधार पर वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन अप्रासंगिक होगा, और इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है या विचार में नहीं लिया जा सकता है। [सोपान सुखदेव साबले बनाम चैरिटी आयुक्त, (2004) 3 एससीसी 137]

23.11 आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की कसौटी यह है कि यदि वाद में किए गए अभिकथनों को पूरी तरह से लिया जाता है, तो जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है, उनके संयोजन में एक डिक्री पारित की जाएगी। यह परीक्षण लिवरपूल और लंदन एस. पी. और आईएसोसिएशन लिमिटेड बनाम एम. वी. सी सक्सेस, (2004) 9 एससीसी 512]

लिवरपूल और लंदन एस. पी. में रखा गया था। & आई एसएन। लिमिटेड v. M.V. सागर सफलता मैं [लिवरपूल और लंदन S.P.] & आई एसएन। लिमिटेड v. M.V. सागर सफलता

I, (2004) 9 एस. सी. सी. 512] जो इस प्रकार हैः (एस. सी. सी. पृष्ठ 562, अनुच्छेद 139)

"139. अभियोग कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है। लेकिन यह करता है या नहीं, यह शिकायत को पढ़ने से ही पता लगाया जाना चाहिए। उक्त प्रयोजन के लिए, वाद में किए गए कथन पूरी तरह से सही माने जाने चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या यदि वाद में किए गए कथन पूरी तरह से सही माने जाते हैं, तो एक डिक्री पारित की जाएगी।

23.12 हरदेश ओरेस (पी) लिमिटेड बनाम हेडे एंड कंपनी [हरदेश ओरेस (पी) लिमिटेड बनाम हेडे एंड कंपनी, (2007) 5 एससीसी 614] वाले मामले में न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि किसी वाक्य या परिच्छेद को निकालने और उसे पृथक रूप से पढ़ने की अनुमति नहीं है। यह पदार्थ है, न कि केवल रूप, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। वाद को शब्दों के जोड़ या घटाव के बिना, जैसा है वैसा ही समझा जाना चाहिए। यदि वादी में आरोप प्रथम दृष्टया कार्रवाई का कारण दिखाते हैं, तो अदालत इस बात की जांच शुरू नहीं कर सकती कि क्या आरोप वास्तव में सही हैं। [डी. रामचंद्रन बनाम आर. वी. जानकीरमन, (1999) 3 एससीसी 267; विजय प्रताप सिंह बनाम दुख हरन नाथ सिंह, एआईआर 1962 एस. सी. 941 भी देखें।

23.13. यदि वाद को सार्थक रूप से पढ़ने पर यह पाया जाता है कि वाद स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और बिना किसी गुण के है, और मुकदमा करने के अधिकार का खुलासा नहीं करता है, तो न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने में न्यायसंगत ठहराया जाएगा।

23.14. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अधीन शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा वाद के किसी भी स्तर पर, या तो वाद दर्ज करने से पहले, या प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद, या विचारण के समापन से पहले किया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एससीसी 557] के निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है। याचिका है कि एक बार मुद्दे तैयार हो जाने के बाद, मामले को वाद को खारिज कर देना चाहिए" यह याचिका कि एक बार मुद्दे तैयार हो जाने के बाद,

मामले को अनिवार्य रूप से मुकदमे में जाना चाहिए, इस अदालत द्वारा अजहर हुसैन मामले में खारिज कर दिया गया था [अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, 1986 पूरक एससीसी 315। इसके बाद मानवेंद्रसिंहजी रंजीतसिंहजी जडेजा बनाम विजयकुंवरबा, 1998 एससीसी ऑनलाइन गुज 281: (1998) 2 जीएलएच 823]।

23.15 आदेश 7 नियम 11 का प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का है। इसमें कहा गया है कि यदि खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट किसी भी आधार को बनाया जाता है तो वाद को खारिज कर दिया जाएगा। यदि अदालत यह मानती है कि वाद कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, या कि वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है, तो अदालत के पास वाद को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

7. सरल शब्दों में, सही परीक्षा सबसे पहले वाद को सार्थक रूप से और समग्र रूप से पढ़ने के लिए होती है, इसे सच मानते हुए। इस तरह पढ़ने पर, यदि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है, तो सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन विफल होना चाहिए। इसे नकारात्मक रूप से रखने के लिए, जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, तो शिकायत को खारिज कर दिया जाएगा।

8. इस स्पष्ट सिद्धांत का पालन करते हुए, अब हम वाद में किए गए कथनों पर विचार करेंगे। शिकायत के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

"वादी का कहना है कि दिवंगत मुनिवेंटकाटा भोवी के उक्त संयुक्त परिवार को सर्वेक्षण संख्या 76/1 में उक्त भूमि के बल पर जब भी आवश्यकता होती थी, फिर नाममात्र बिक्री विलेख निष्पादित करके 76/2 के रूप में पुनः गणना की जाती थी और उसी को साफ़ करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता था... वही आदत स्वर्गीय मुनिवेंटकाटा भोवी की उनकी पत्नियों द्वारा मृत्यु के बाद भी जारी रही... उक्त लैंडिंग सर्वेक्षण संख्या 76/2 हमेशा जारी रही और वादी के संयुक्त परिवार के कब्जे में है.... वादी का कहना है कि कई बार उक्त वितपोषकों के बकाया ऋणों को चुकाने के बाद भी, वादी के संयुक्त परिवार के पक्ष में उसके पक्ष में पुनर्खरीद विलेख या रिहाई विलेख थे क्योंकि उन्हें करीबसप्पा के परिवार में अपार विश्वास था और उक्त संयुक्त परिवार की संपत्तियों पर उनके संयुक्त कब्जे के बारे में कोई परेशानी नहीं थी...

वादी का कहना है कि वादी के कल्याण के प्रति प्रतिवादी 1 से 3 का रवैया उदासीन हो गया और उन्होंने उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया... कुछ वादी ने कुछ कदम उठाने के लिए प्रतिवादी 1 से 3 बनाने की कोशिश की... उक्त प्रतिवादी 1 से 3 ने उन्हें और अन्य वादी को धैर्य रखने की सलाह दी क्योंकि मुकदमे की अनुसूची की संपत्तियों को विभाजित करने से पहले बहुत सारे दस्तावेजों और राजस्व प्रविष्टियों को अद्यतन किया जाना चाहिए और वादी सहित प्रत्येक हिस्सेदार को अलग कब्जा देना चाहिए...

वादी का कहना है कि उक्त संयुक्त परिवार पर कोई ऋण नहीं है और मुकदमा अनुसूची संपत्तियां विभाजन के लिए उपलब्ध हैं...

वादी की धारा 1 से 6 में कहा गया है कि उक्त वाद अनुसूची संपत्तियों को वादी और प्रतिवादी 1 से 3 के बीच विभाजित करने के बजाय, उक्त प्रतिवादियों ने मई 2005 के महीने में इसे दूसरों से अलग करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है... उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि करीबप्पा के उत्तराधिकारी और स्वयं उनसे पूछताछ करने की हिम्मत करने के लिए वादी के लिए सभी प्रकार की समस्याएं पैदा करेंगे और उन्होंने दावा किया कि वाद अनुसूची संपत्तियों और राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में कई दस्तावेज बनाए गए हैं और अपने स्वयं के व्यक्ति के नाम पर बनाए गए हैं और वे वादी को अपने शेयरों को प्राप्त करने में सभी प्रकार की बाधाएं पैदा करेंगे और यहां तक कि इसमें तीसरे पक्ष के हित भी पैदा करेंगे और दूसरों को इसके कब्जे में शामिल करेंगे..."

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वादी की विशिष्ट दलील थी कि विभिन्न बिक्री 'नाममात्र बिक्री विलेखों' के माध्यम से निष्पादित की गई थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। विशेष रूप से संयुक्त परिवार की संपत्ति की शिकायत ने राजस्व रिकॉर्ड के मुद्दे को संबोधित किया और कहा कि हालांकि आर. टी. सी. रिकॉर्ड वितपोषकों के नाम पर थे, संयुक्त परिवार संपत्ति के निर्बाध कब्जे में बना रहा।

9. यदि वादपत्र में दिए गए कथन सत्य माने जाते हैं, तो संयुक्त परिवार की संपत्तियों से उसके सदस्यों को लाभ हो सकता है और वे विभाजन के लिए अच्छी तरह से उपलब्ध हो सकती हैं। यह विचारण का विषय है, जिसका परिणाम वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर निर्भर करेगा। इस स्तर पर, हम अभिकथनों की शुद्धता से चिंतित नहीं हैं, सिवाय यह कहने के

कि वादी के पास कार्यवाही का संचालन है, और उन्हें अपने मामले को साबित करने के भारी बोझ का निर्वहन करना है। जहां तक सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन का संबंध है, यह न्यायालय केवल उस हद तक आगे बढ़ेगा, यह जांचने के लिए कि क्या वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है, और आगे नहीं।

10. उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष की जांच करके एक त्रुटि की। इसने बिक्री विलेख की सच्चाई, वैधता और वैधता का पूर्व निर्णय लिया जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 4 से 14 दावा शीर्षक। इसका मतलब यह नहीं है कि वादी पर अपने मामले को साबित करने का कोई कम बोझ है या यह भी कि उनका मामला संभावित है। सीधे शब्दों में कहें तो, उच्च न्यायालय यह मानकर दावों की सच्चाई का अनुमान नहीं लगा सकता था कि संपत्ति की कथित पिछली बिक्री पूरी हो गई है या उस पर कार्रवाई की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण गलत है और आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत एक आवेदन पर विचार करने के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं और आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत आवेदन को खारिज करते हैं, और शिकायत की अनुसूची ए के तहत उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में भी वाद को बहाल करते हैं।

11. एक और कारण है कि उच्च न्यायालय का निर्णय टिकाऊ नहीं है। आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन में, सीपीसी एक शिकायत को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है और मकसूद अहमद बनाम मथरा दत्त एंड कंपनी 4 में 1936 के फैसले के बाद से लगातार इसका पालन किया जा रहा है। इस सिद्धांत को सेजल ग्लास लिमिटेड बनाम नविलन मर्चेंट्स (पी) लिमिटेड, 5 में इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय में भी समझाया गया है, जिसका माधव प्रसाद अग्रवाल बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड. 6 में फिर से पालन किया गया था। माधव प्रसाद (उपर्युक्त) का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया हैः

"10. हम अन्य सभी तर्कों पर विस्तार करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि हम अपीलार्थी(ओं) की आपत्ति को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद की अस्वीकृति की राहत केवल प्रतिवादी(ओं) में से एक के संबंध में नहीं की जा सकती है।

दूसरे शब्दों में, आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, वाद को समग्र रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। वास्तव में, विद्वत एकल न्यायाधीश ने उसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा करके अपीलार्थी(ओं) द्वारा उठाई गई इस आपत्ति को खारिज कर दिया। हालांकि, हमें लगता है कि सेजल ग्लास लिमिटेड [सेजल ग्लास लिमिटेड बनाम नविलन मर्चेंट्स (पी) लिमिटेड, (2018) 11 एससीसी 780: (2018) 5 एससीसी (सीवी) 256] में इस अदालत का निर्णय सीधे बिंदु पर है। उस मामले में, आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के तहत प्रतिवादी(ओं) के नेतृत्व में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि वादी ने कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया था। दीवानी अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि वाद को विभाजित किया जाना है क्योंकि इसने निदेशक के प्रतिवादी(ओं) 2 से 4 के खिलाफ कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया है। उस आधार पर, उच्च न्यायालय ने राय दी थी कि मुकदमा केवल प्रतिवादी 1 कंपनी के खिलाफ जारी रह सकता है। इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया प्रश्न यह था कि क्या आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई मार्ग सिविल न्यायालय के लिए खुला है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर कई निर्णयों का समर्थन करते हुए उक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया, जिसमें लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वाद को या तो समग्र रूप से अस्वीकार किया जा सकता है या बिल्कुल नहीं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाद के किसी विशेष भाग के लिए वाद को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं है, जिसमें कुछ प्रतिवादी(ओं) के खिलाफ भी शामिल है और दूसरों के खिलाफ इसे जारी रखने की अनुमति नहीं है। न्यायालय ने अनिश्चित शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि वाद कुछ प्रतिवादी(ओं) और/या संपत्तियों के विरुद्ध जीवित रहता है, तो आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा, और समग्र रूप से वाद को तब विचारण के लिए आगे बढना चाहिए...

12. निर्विवाद रूप से, आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन न करने या आदेश 7 सीपीसी के नियम 11 के खंड (क) से (च) के लिए वाद प्रस्तुत करते समय किसी भी संस्थागत अवज्ञा से परिपूर्ण होने के कारण वाद को खारिज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किए गए वाद को समग्र रूप से आगे बढना चाहिए या समग्र रूप से अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन आंशिक रूप से नहीं..."

(जोर दिया गया)

12. उपर्युक्त निर्दिष्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अनुसूची-क संपत्ति के संबंध में आंशिक रूप से वाद को अस्वीकार करने और वादी को मुकदमा चलाने की अनुमति देने में त्रुटि की है केवल अनुसूची-ख संपत्ति के संबंध में मामला। आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय यह दृष्टिकोण अस्वीकार्य है। इसलिए हम इस आधार पर भी उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

13. ऊपर बताए गए कारणों से, एसएलपी (सी) संख्या 8147/2016 से उत्पन्न सिविल अपील की अनुमति दी जाती है और सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 158/2010 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 09.11.2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को निरस्त किया जाता है।

14. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान कार्यवाही एक मुकदमे से उत्पन्न हुई है 2005 में स्थापित, हम वाद को विचारण न्यायालय से शीघ्रता से मुकदमा चलाने और निपटाने का अनुरोध करते हैं।

15. पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्य पांडे द्वारा तैयार की गईं। अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक (मदन मोहन प्रिय) के द्वारा किया गया है।